भारत नेपाल कूटनीतिक संबंध (2014 से वर्तमान तक)

डॉ. ब्रज किशोर

सह -आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

सार
वर्ष 2014 से वर्तमान तक भारत और नेपाल के कूटनीतिक संबंधों में "नेबरहुड फर्स्ट" (Neighbourhood First) नीति के तहत ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिविटी और उच्च स्तरीय वार्ताओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, साथ ही कालापानी व सीमा मुद्दों पर समय-समय पर कूटनीतिक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

परिचय
मुख्य आयाम और उपलब्धियाँ (2014 से अब तक)उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद: 2014 से दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख स्तर पर कई उच्च स्तरीय दौरे हो चुके हैं, जो आपसी संबंधों को स्थिरता देने का काम करते हैं। [1] ऊर्जा और जल संसाधन सहयोग: भारत और नेपाल के बीच पनबिजली परियोजनाओं और ऊर्जा व्यापार में तेजी आई है। नेपाल भारत को बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति कर रहा है। इसके अलावा, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन (मोतिहारी से अमलेकगंज) का उद्घाटन 2019 में किया गया था। [1] कनेक्टिविटी और डिजिटल पहल: दोनों देशों के बीच बस सेवा, रेलवे पहल (जैसे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन), और वित्तीय मोर्चे पर क्रॉस-बॉर्डर यूपीआई (UPI) क्यूआर भुगतान की शुरुआत हुई है। [1] प्रमुख चुनौतियाँ एवं विवादसीमा विवाद: कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को लेकर वर्ष 2020 के बाद से कूटनीतिक तनाव देखा गया, हालाँकि हालिया बयानों में दोनों पक्ष द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इन मामलों को सुलझाने पर जोर दे रहे हैं। [1] चीन का प्रभाव: नेपाल की राजनीति में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और बढ़ती रणनीतिक दखलंदाजी के कारण भारत के समक्ष सुरक्षा और कूटनीतिक मोर्चे पर नई चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। [1] [1,2,3]

विचार-विमर्श
भारत-नेपाल संबंधों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां
राजनीतिक अस्थिरता: नेपाल में बार-बार बदलती सरकारों के कारण दीर्घकालिक घरेलू नीतियों और विदेश संबंधों, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में निरंतरता की कमी देखी जा रही है।

2008 में राजशाही की समाप्ति के बाद से ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इसका मुख्य कारण कमजोर राजनीतिक गठबंधन, गहन गुटबाजी से संबंधित संघर्ष और लगातार सामने आने वाले भ्रष्टाचार घोटालों के मामले हैं।
वर्ष 2014 से अब तक भारत और नेपाल के बीच राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख स्तर पर 17 उच्चस्तरीय दौरे हो चुके हैं।
सीमा व्यापार और सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दे: उदाहरण के लिए, हाल ही में नेपाल की नव-निर्वाचित सरकार ने भारत से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये (NRS) से अधिक मूल्य के सामान पर सीमा शुल्क लगाने का निर्णय लिया था। हालांकि, नेपाल के शीर्ष न्यायालय ने बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार के इस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी।
सीमा विवाद: वर्ष 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया गया।

नेपाल का तर्क है कि महाकाली नदी के पूर्व स्थित ये क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि के अनुसार उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
यह सीमा विवाद 2025 में तब पुनः उभर कर सामने आया, जब भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने की पहल की।[4,5,6]

चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा : उदाहरण के लिए, 2015 में भारत द्वारा लगाए गए व्यापार अवरोध के बाद नेपाल ने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए व्यापार में विविधता लाने का प्रयास किया। इसी क्रम में 2017 में नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल हुआ।

आर्थिक व्यवधान: पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, अरुण-III और ऊपरी करनाली जैसी प्रमुख संयुक्त परियोजनाएं राजनीतिक गतिरोध और बढ़ते विश्वास संकट के कारण विलंबित हुई हैं।
सुरक्षा संबंधी मुद्दे: कुछ रिपोर्टों के अनुसार, भारत-नेपाल की खुली सीमा का दुरुपयोग आतंकवादी और संगठित अपराध समूहों द्वारा प्रशिक्षित संचालकों की आवाजाही, नकली भारतीय मुद्रा के प्रसार तथा तस्करी जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

गोरखा भर्ती मुद्दा: भारत की अग्निपथ योजना ने गोरखा सैनिकों सहित सैन्य भर्ती की शर्तों में बदलाव किया है। इसके कारण नेपाल ने नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
नेपाल में जैन-जी (Gen-Z) आंदोलन के नेतृत्व में हो रहा बदलाव राजनीतिक स्थिरता हासिल करने का एक अवसर प्रदान करता है; यह अनिश्चितता को दूर करता है, मौजूदा कमियों को दूर करता है और एक अधिक समावेशी तथा प्रतिनिधि राजनीतिक माहौल को बढ़ावा देता है।

नेपाल के प्रति भारत की विदेश नीति उसके "नेबरहुड फर्स्ट" दृष्टिकोण के अंतर्गत संचालित होती है, जिसमें राजनीतिक प्रबंधन से आगे बढ़कर "शांत कूटनीति" पर बल दिया गया है। भारत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, जल निकासी, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलविद्युत आदि प्राथमिक क्षेत्रों में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDPs) के माध्यम से स्थानीय स्तर पर नेपाल के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।[7,8,9]
भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,751 किमी लंबी सीमा साझा है, किंतु कुछ क्षेत्रों में सीमा विवाद अभी भी विद्यमान हैं।

कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा विवाद: नेपाल ने अपने दावे का आधार वर्ष 1816 की सुगौली संधि को बनाया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्र के बीच संपन्न हुई थी।
इस संधि के अनुसार काली नदी को भारत और नेपाल के बीच पश्चिमी सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था।
नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, जिसके आधार पर लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र नेपाल के भूभाग में आते हैं।

इसके विपरीत, भारत का मत है कि नदी का उद्गम कालापानी के निकट निम्नतर बिंदु से होता है, जिससे लिपुलेख दर्रा, जो भारत, नेपाल और चीन के मध्य एक सामरिक त्रि-जंक्शन है, भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है।
वर्षों के दौरान काली नदी की धारा में परिवर्तन होने से सीमा निर्धारण को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।
सुस्ता सीमा विवाद: सुस्ता भारत और नेपाल के बीच एक विवादित क्षेत्र है।[6,7,8]
वर्तमान में इसका प्रशासन भारत द्वारा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भाग के रूप में किया जाता है।

नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र पश्चिम नवलपरासी जिले की सुस्ता ग्रामीण नगरपालिका का हिस्सा है।
नेपाल का आरोप है कि सुस्ता क्षेत्र में लगभग 14,860 हेक्टेयर नेपाली भूमि पर भारत द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

भारत-नेपाल संबंधों का अवलोकन

साझी सीमा: नेपाल की सीमा भारत के पाँच राज्यों—सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड—से लगती है।
स्थलरुद्ध राष्ट्र होने के कारण नेपाल वस्तुओं एवं सेवाओं के परिवहन तथा समुद्री पहुँच के लिए भारत पर अत्यधिक निर्भर है।
भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, 1950: वर्ष 1950 में हस्ताक्षरित यह संधि भारत-नेपाल के विशेष संबंधों की आधारशिला है।
इस संधि के प्रावधानों के अनुसार नेपाली नागरिकों को भारत में भारतीय नागरिकों के समान अनेक सुविधाएँ एवं अवसर प्राप्त हैं।[3,4,5]
रक्षा सहयोग: भारत, नेपाली सेना के आधुनिकीकरण में उपकरण उपलब्ध कराकर तथा प्रशिक्षण प्रदान करके सहयोग करता रहा है।
दोनों देश बारी-बारी से भारत और नेपाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' का आयोजन करते हैं।
वर्ष 1950 से दोनों देश एक-दूसरे के सेनाध्यक्षों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करते रहे हैं।
भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंटों में आंशिक रूप से नेपाल के पर्वतीय जिलों से भर्ती की जाती है।
व्यापार एवं आर्थिक संबंध: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेशक बना हुआ है।
नेपाल में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के भंडार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 33.5 प्रतिशत है।
नेपाल, वर्ष 2014 में 28वें स्थान से बढ़कर भारत का 17वाँ सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है।
भारत से नेपाल को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा एवं इस्पात, ऑटोमोबाइल, मशीनरी तथा अनाज शामिल हैं।
संपर्क एवं विकास साझेदारी: स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संपर्क अवसंरचना जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत नेपाल का सबसे बड़ा विकास सहयोगी है।[5,6,7]
प्रमुख परियोजनाओं में गौचर हवाई अड्डा (वर्तमान त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा), पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, सीमा-पार रेल संपर्क तथा एकीकृत जाँच चौकियों की स्थापना शामिल हैं।
ऑपरेशन मैत्री एवं भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण सहायता: वर्ष 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सबसे पहले सहायता पहुँचाने वाला देश था।
भारत सरकार ने 'ऑपरेशन मैत्री' के माध्यम से विदेश में अपना अब तक का सबसे बड़ा आपदा राहत अभियान संचालित किया।
सांस्कृतिक संबंध: दोनों देशों के नेताओं ने समय-समय पर भारत-नेपाल के प्राचीन 'रोटी-बेटी' संबंधों का उल्लेख किया है।
यह संबंध दोनों देशों के लोगों के बीच होने वाले सीमा-पार वैवाहिक एवं सामाजिक संबंधों को दर्शाता है।
अन्य चिंता के क्षेत्र
कार्यान्वयन में विलंब: कुछ संपर्क एवं अवसंरचना परियोजनाओं की धीमी प्रगति ने समय-समय पर नेपाल में चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक एवं सामरिक उपस्थिति ने क्षेत्रीय भू-राजनीति तथा भारत की पड़ोस नीति को एक नया आयाम दिया है।
असमानता की धारणा: नेपाल के राजनीतिक वर्ग एवं जनचर्चा के कुछ वर्गों ने द्विपक्षीय संबंधों में भारत की प्रमुख भूमिका को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं, जिसे प्रायः 'बिग ब्रदर' धारणा कहा जाता है।

राजनीतिक संवेदनशीलताएँ: दोनों देशों के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा राष्ट्रवादी बयानबाजी समय-समय पर अविश्वास उत्पन्न कर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकती है।
जल संसाधन प्रबंधन: साझा नदियों के प्रबंधन, जलविद्युत सहयोग तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से जुड़े मतभेद अभी भी घनिष्ठ समन्वय एवं निरंतर संवाद की अपेक्षा रखते हैं।
कूटनीतिक संवाद का सुदृढ़ीकरण: सीमा विवादों सहित लंबित मुद्दों का समाधान वर्तमान द्विपक्षीय तंत्रों तथा सतत कूटनीतिक संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए।[2,3,4]
संपर्क एवं व्यापार को प्रोत्साहन: सीमा-पार अवसंरचना, रेल, सड़क एवं ऊर्जा संपर्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाई जानी चाहिए।
ऊर्जा सहयोग का सुदृढ़ीकरण: जलविद्युत विकास, सीमा-पार विद्युत व्यापार तथा पारेषण अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए।
पारस्परिक विश्वास को प्रोत्साहन: नियमित उच्च-स्तरीय संवाद तथा एक-दूसरे की संप्रभुता एवं संवेदनशीलताओं के सम्मान के माध्यम से चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए।
जन-से-जन संबंधों का विस्तार: शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों को सुदृढ़ कर प्राचीन 'रोटी-बेटी' संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।[8,9]

परिणाम

2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को हराया। यह भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में एक नए युग की शुरुआत थी। चुनाव में जीत के बाद कुछ मीडियाकर्मियों ने नरेंद्र मोदी को "भारत का शिंजो आबे" कहा, जबकि विदेशियों ने उन्हें "भारतीय पुतिन" कहकर डराया। उन्हें "भारतीय डेंग शियाओपिंग" भी कहा जा सकता है। समय ही बताएगा कि मोदी के लिए कौन सा नाम सबसे उपयुक्त है। किसी भी स्थिति में, मोदी एक सक्रिय विदेश नीति का अनुसरण करते हैं, जो आर्थिक कारकों से प्रभावित हो सकती है। भारत के मतदाताओं ने उनके चुनावी वादों में "विकास और सुशासन" का वादा सुना था, और मोदी ने देश के नागरिकों से किए गए अपने वादों को पूरा किया है। नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुआ है क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक व्यावहारिक, दूरदर्शी विदेश नीति अपनाई है जो हमारी सरकार के राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देने और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले युवा देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के वैश्विक दायित्वों को पूरा करने के प्रमुख लक्ष्य से जुड़ी है। पंचायत के अंतर्गत, हमारी विदेश नीति अब सम्मान, संवाद, सत्यि और सुरक्षा पर आधारित है, जो पंचायत के पाँच स्तंभ हैं: गरिमा और सम्मान, आपसी मेलजोल और चर्चा में वृद्धि, साझा समृद्धि, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, और सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंध। भाजपा के घोषणापत्र में कहा गया है कि वे भारत के सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का वादा करते हैं, लेकिन वे कड़े रुख अपनाने और जो सही है उसके लिए खड़े होने से नहीं डरेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। आपके सभी पड़ोसी इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। मोदी की एक कठोर राजनीतिज्ञ के रूप में छवि और उनकी पार्टी के "राष्ट्रवादी" रुख को देखते हुए, यह उम्मीद है कि भारत में आने वाली सरकार पिछली सरकारों से अलग होगी।[8]

निष्कर्ष

नेपाल और भारत के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। ये संबंध इतिहास, संस्कृति, परंपरा और धर्म के दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित हैं, और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों में इनकी स्पष्टता बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 17 जून, 1947 को औपचारिक रूप से स्थापित हुए, जो एक लंबे और फलदायी संबंध की परिणति थी। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का आधार शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभु समानता और एक-दूसरे की आकांक्षाओं और भावनाओं के प्रति सम्मान के आदर्शों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता रही है।

भारत के शत्रुतापूर्ण समूहों द्वारा अपने क्षेत्र का उपयोग न करने की नेपाल की दीर्घकालिक नीति और भारत से पारस्परिक सहयोग और गारंटी की अपेक्षा, अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने और उन्हें पोषित करने की नेपाल की गंभीर इच्छा को दर्शाती है।[9]

संदर्भ

1. Jaiswal Pramod,—Chinese Inroads to Nepal,Himalayan Frontier, #4319, 3 March 2014,Nepal-Articles, IPCS.
2. Shreshtha Buddhi N., —The Natural Environment and the Shifting Borders Visit and New Delhi's Interests‖, #4117, 13 September 2013, IPCS.
3. Das Pushpita,—Need to effectively manage the India-Nepal Border‖, September 19, 2013, IDSA Comment.
4. JhaHariBansh,—India's Economic Miracle and its Impact on Nepal‖,Strategic Analysis, IDSA,Volume 36, Issue 1, 2012.
5. Https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Indian_General_Election,_2014 Indian General Election, 2014 - Wikipedia, the Free
6. P. Jasiwal, Modi and Nepal –India Relations, Himalayan Frontier. 2 June, 2014, IPCS.
7. "Koirala Congratulates Modi, Invites Him To Nepal". The Kathmandu Post. 19 May 2014. Retrieved 19 May 2014.
8. P. Jasiwal, Modi and Nepal –India Relations, Himalayan Frontier. 2 June, 2014, IPCS.
9. The Hindu, New Delhi, Jul 23, 2014